Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

13 अगस्त 2018

पॉपुलर फ्रंट की नेशनल जनरल असेंबली समाप्त

आरएसएस से देश को बचाने के लिए महागठबंधन और संयुक्त चुनावी रणनीति अपनाने की अपील

असम में एनआरसी का दुरूपयोग न करने और नागरिकता बिल वापस लेने की मांग

बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ और राफेल घोटाले में जांच की मांग

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल जनरल असेंबली (एनजीए) 10 से 12 अगस्त 2018 को केरल के मलप्पुरम में स्थित मालाबार हाउस में आयोजित हुई, जिसकी समाप्ती पर सभी सेक्युलर व लोकतांत्रिक दलों और पीड़ित वर्गों के आंदोलनों से 2019 के लोकसभा चुनावों में आरएसएस को सत्ता से दूर रखने के लिए हर राज्य और हर चुनावी क्षेत्र में एक संयुक्त राजनीतिक प्रतिरोध बनाने की अपील की गई। असेंबली के समापन सत्र में विभिन्न राष्ट्रीय स्तरीय मामलों पर प्रस्ताव भी पास किये गए।

असेंबली यह समझती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और इस सेक्युलर लोकतांत्रिक देश भारत के इतिहास में निर्णायक साबित होंगे। बीजेपी राज में देश के मौजूदा हालात हमें यह बताते हैं कि सही सोच रखने वाले लोगों के सामने देश को साम्प्रदायिक फासीवादी संघ परिवार के कंट्रोल से बचाने का यह अंतिम मौका हो सकता है। केंद्र सरकार हर मैदान में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, इसलिए बीजेपी अपने साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के असल एजेंडे की तरफ लौट आई है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला बोल दिया है। असेंबली का मानना है कि: ''सभी सेक्युलर पार्टियों के लिए वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वे अपासी मतभेद को एक तरफ रखकर 2019 के आम चुनावों में बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक संयुक्त प्लेटफार्म बनाएं। संयुक्त विपक्ष के बारे में कई नेताओं के बयान समने आए हैं लेकिन दुर्भाग्य से उसको अब तक अमली रूप नहीं दिया जा सका है। कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि विपक्षी पार्टियों ने आपसी समझौता करने और देश के बड़े फायदे के लिए एक प्लेटफार्म पर आने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। सभी सेक्युलर दलों के लिए सेक्युलरिज़्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने की यह महत्वपूर्ण घड़ी है। पॉपुलर फ्रंट की एनजीए सभी सेक्युलर दलों से 2019 के आम चुनावों में एक संयुक्त प्लेटफार्म बनाने हेतु कुर्बानी के लिए तैयार रहने की अपील करती है।''

नेशनल जनरल असेंबली द्वारा पारित एक दूसरे प्रस्ताव में असम में एनआरसी को निष्पक्ष रूप से लागू करने और जान बूझकर भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को खारिज करने के

मकसद से एनआरसी की प्रक्रिया में छेड़छाड़ बंद करने की असामी जनता की मांग के समर्थन की बात कही गई। असेंबली ने डी–वोटरों की सभी कार्यवाहियों और व्यवस्था को खत्म करके उन सबको एनआरसी प्रक्रिया में शामिल करने की भी मांग की। प्रस्ताव में यहा कहा गया किः ''30 जुलाई 2018 को जारी असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मसौदे ने राज्य में बहुत ही गंभीर हालात पैदा कर दिये हैं और बहुत जल्द इसके बुरे परिणाम देश के दूसरे राज्यों में भी नज़र आएंगे। असम की कुल आबादी में से 40 लाख से अधिक लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने तक बेवतन करार दिया गया है।'' असेंबली ने केंद्र सरकार से संसद में मौजूद नागरिकता (संशोधन) बिल को वापस लेने की भी मांग की है, क्योंकि भारतीय संविधान की रूह के खिलाफ यह बिल नागरिकता देने के लिए धर्म को मापदंड करार देता है।

नेशनल जनरल असेंबली ने देश में विशेषकर बीजेपी शासित उत्तरी राज्यों में गाय के नाम पर भीड़तंत्र की बढ़ती हिंसक घटनाओं पर गहरा दुख और चिंता जताई है। असेंबली ने भीड़तंत्र की हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए ज़मीनी स्तर पर प्रतिरोध और मज़बूत क़ानूनी लड़ाई की अपील की। असेंबली ने राफेल घोटाले में जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार कथित रूप से शामिल हैं, निष्पक्ष जांच की मांग की है। एक दूसरे प्रस्ताव में बैठक ने सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद मामले में हिंदुत्व ताकतों को राजनीतिक लाभ उठाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप की अपील की है। असेंबली ने पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों से केरल के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने की भी अपील की है।

एनजीए ने, जिसका उद्घाटन चेयरमैन ई. अबूबकर द्वारा किया गया, संगठन की पिछले डेढ़ साल की गतिविधियों का जायज़ा लिया और आने वाले दिनों में संगठन के काम काज पर चर्चा की। महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना ने गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की जिस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रिपोर्ट में सदस्यता बढ़ाने और विशेष रूप से उत्तरी राज्यों के नए इलाकों में संगठन के विस्तार में पॉपुलर फ्रंट के सदस्यों और कार्यकर्ताओं की कुर्बानियों की सराहना की गई। एनजीए में विभिन्न राज्यों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो वाइस चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम के भाषण के साथ समाप्त हुई।

एम. मुहम्मद अली जिन्ना
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया